'आप' की एतिहासिक जीत और अरविंद केजरीवाल से अपेक्षाएं

-मनोज कुमार झा

दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली जीत ऐतिहासिक है। यह अप्रत्याशित भी है। स्वयं अरविंद केजरीवाल ने भी यह नहीं सोचा होगा कि उन्हें 67 सीटें मिल जाएंगी। ज़्यादातर चुनाव पूर्ण सर्वेक्षणों में उनकी जीत को सुनिश्चित तो माना गया था, पर कांग्रेस के साथ भाजपा का भी एक तरह से सूपड़ा साफ़ हो जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। बहरहाल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की यह जीत केन्द्र की भाजपा सरकार और नरेन्द्र मोदी के लिए बहुत बड़ा सबक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जनता ने दिखा दिया कि उसे खोखले वायदों और हवा-हवाई घोषणाओं पर यकीन नहीं है। साथ ही, बेहतर विकल्प मिलने पर वह उसे अपनाने से नहीं चूकेगी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। साथ ही, प्रचार के दौरान उन्होंने लोकतंत्र को मर्यादाओं को धता बताते हुए अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ ओछे किस्म का प्रचार किया और हर संभव हथकंडा अपनाया। लेकिन बीजेपी का महज तीन सीटों पर सिमट कर रह जाना यह दिखा देता है कि आने वाले दिनों में मोदी को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब थोथी घोषणाओं और झूठे वायदों पर जनता यकीन नहीं कर सकती। नौ माह में ही लोगों को भाजपा सरकार की हक़ीक़त ठीक से पता चल गई है। नरेन्द्र मोदी की सरकार ने इतने दिनों में एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता को जरा भी राहत मिली हो, उलटे संघ परिवार के लोगों ने सांप्रदायिक घृणा फैलाने की पुरज़ोर कोशिश की, जिसे मोदी का मौन समर्थन मिलता रहा। मोदी ने जिस भगवा आतंक को फैलाने की कोशिश की और देश के अल्पसंख्यकों में भय का माहौल बनाना चाहा, उसकी आलोचना अेतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी की है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश की गरिमा के ख़िलाफ़ बयानबाज़ी की है, जिसे भूला नहीं जा सकता। जो भी हो, दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया है। भाजपा की नीति थी कि हार की हालत में इसका ठीकरा सीएम कैंडिडेट किरण बेदी पर फ़ोड़ा जाएगा, पर बेदी ने भी साफ़ कहा कि हार के लिये भाजपा जिम्मेदार है। वहीं, भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी मोदी को ही हार के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है।

दिल्ली में मोदी की हार के निहितार्थ बहुत गहरे हैं। दिल्ली की जनता देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। उसके द्वारा भाजपा को नकारा जाना हलके में नहीं लिया जा सकता। आने वाले दिनों में

जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां मोदी की इस हार का असर पड़ना लाजिमी है। बहुत जल्दी ही मोदी की हवा निकल गई। यह देश और जनता के हित में है। साथ ही, दल्ली में केजरीवाल की जीत से उन दलों को भी सबक लेने की जरूरत है, जिन्हें निकट भविष्य में जल्दी ही चुनाव का सामना करना है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टियों को यह सोचना ही होगा कि उनकी नीतियों में क्या खामियां हैं और कैसे वे मोदी को पराजित कर सकते हैं। देशहित में मोदी को रोकना ही अन्य दलों के सामने एकमात्र चुनौती है। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का सत्तारूढ़ नेतृत्व दिल्ली विधानसभा चुनाव से कोई सबक लेगा, क्योंकि वह भ्रष्टाचार में डूबा है, जातिवाद और अल्पसंख्यकवाद चुनाव जीतने का उसका मुख्य आधार रहा है। साथ ही, अपराधियों को बढ़ावा देना इस नेतृत्व की शुरू से ही फ़ितरत रही है, जिससे ये बाज़ नहीं आ सकता, तो मोदी की चुनौती का समना कर पाना भी इसके वश की बात नहीं। बिहार में अभी जो राजनीतिक संकट और अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई है, उससे साफ़ है कि क्षत्रप मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, तो वह मोदी की चुनौती का सामना कर पाने में इसलिए सफल हो पाए, क्योंकि उन्होंने मुद्दा आधारित राजनीति की, वोटरों को बरगलाया नहीं, झूठे वायदे नहीं किए और जो भी कहा वह इस अंदाज़ में कि जनता को उनसे अपनापन महसूस हुआ। परिणाम सामने है। भूलना नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ़ ग़रीब तबकों का ही समर्थन नहीं मिला है, बल्कि मध्यवर्ग भी उनके साथ रहा है। तभी वे 67 सीटें जीत सके। अब अगर अन्य दल इसका सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण कर पाने में असफल रहते हैं, तो उनका वही हाल होगा जो कांग्रेस का हुआ। निकट भविष्य में वे एक भी सीट जीत पाने के काबिल नहीं रह जाएंगे।

अरविंद केजरीवाल को मोदी विरोधी सभी दलों के अलावा वामपंथियों का समर्थन भी मिला, जिनकी हैसियत भारतीय राजनीति में अब कुछ खास नहीं रह गई है। इस समर्थन से अरविंद केजरीवाल को कितना लाभ हुआ, इसका आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि अगर इनकी कुछ ताकत रह गई होती तो लोकसभा चुनावों में ये इस तरह मार नहीं खाते। बहरहाल, समर्थन देने के अलावा भी उनके पास कोई चारा नहीं था। वैसे, लगता तो यही है कि उनका समर्थन नहीं भी मिला होता तो भी अरविंद केजरीवाल को ही विजय हासिल होती, क्योंकि जनता मोदी के लटकों-झटकों से आजिज आ चुकी थी। सिर्फ़ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश की जनता का मोदी से मोहभंग हो चुका है। अगर अभी चुनाव हों तो परिणाम सामने आ जाए। भाजपा और मोदी को औंधे मुंह गिरने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आसुरी शक्तियों का यह प्रतिनिध पांच साल तो देश की जनता की छाती पर मूंग दलेगा ही, अरविंद केजरीवाल को भी परेशान करने से बाज़ नहीं आएगा। वैसे, दिखाने के लिए मोदी और उनके सहयोगियों ने अरविंद केजरीवाल का सहयोग करने की बात की है। पर भूलना नहीं होगा कि ये वही लोग हैं जो उन्हें नक्सलवादी बता रहे थे और जंगलों में जाने की सलाह दे रहे थे। अब जब 70 में कुल 3 सीटें मिलीं और मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार भी हार गईं तो सहयोग करने का झूठा आश्वासन दे रहे हैं। वास्तव में वे अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए नित नई समस्याएं पैदा करने से बाज नहीं आएंगे और केजरीवाल को उनका सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल इन बातों को नहीं समझ रहे होंगे। पर उन्हें इनकी काट के लिए पक्की रणनीति तैयार करनी होगी। इस बात में दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल सुधारवादी नेता हैं। वह वर्तमान संवैधानिक ढांचे में ही रहकर जनहित के काम करना चाहते हैं, राजनेताओं-पूंजीपतियों की लूट-खसोट पर अंकुश लगाना चाहते हैं, जनता को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना चाहते हैं, जो कहीं से ग़लत नहीं कही जा सकती। जनता को संविधान प्रदत्त सुविधाएं मिलनी ही चाहिए, ये नहीं मिल पा रही क्योंकि लुटेरे तत्वों ने हर जगह सत्ता पर कब्ज़ा जमा रखा है। अगर अरविंद केजरीवाल जनता को उसका हक़ दिला पाने में कामयाब होते हैं, तो इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। पर इसके लिए उन्हें उन तत्वों से सावधान रहना होगा, जो सत्ता के लालच में उनके आसपास आ जाते हैं। ये कैसे तत्व हैं, इसका पता तो अरविंद केजरीवाल को चल ही गया होगा। अगर वो अभी भी सावधान नहीं रहे, तो आगे परेशानी झेलनी पड़ सकती है। कुछ अवसरवादी सत्तालोभी तत्व तो उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं और अब राजनीति में कहीं के नहीं रहे, पर अभी भी कुछ संदिग्ध लोग उनके आसपास हैं, जो कभी भी उन्हें धोखा दे सकते हैं और उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये केजरीवाल पर ही है कि वो उनसे पीछा छुड़ाते हैं या नहीं। वैसे, उनके पास ऐसा बंपर बहुमत है कि पांच साल तक तो कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन तय है कि अगर वे जनहित के मुद्दों को आगे बढाने में लगे तो कॉरपोरेट और अपराधी तत्व में बदल गए राजनीतिकों से उन्हें कड़ी टक्कर लेनी पड़ेगी। चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें कई क्षेत्रों में पूर्णाधिकार हासिल नहीं है, इसलिए उन्हें कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को ग्लैमर जगत की हस्तियों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनका जो वर्ग चरित्र है, वह जनविरोधी ही होता है। ये अपने निजी स्वार्थ के लिये किसी से जुड़ते या दूर होते हैं। केजरीवाल को अधिक से अधिक सामान्य जन से जुड़ने की कोशिश करनी होगी, तभी वो सफल हो सकते हैं। कुछ उग्र वामपंथी तत्व जिनका कोई ज़मीनी आधार नहीं और जो सिद्धांतों की लफ़्फ़ाजी करते हैं, अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं। ये करेंगे कुछ नहीं और अगर कोई कुछ सुधारवादी प्रयास करता है, तो उसका भी पुरजोर विरोध करेंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या क्रांति सीधे आसमान से उतरेगी। उन्ही लोगों ने भारतीय जनता के आन्दोलन को दम भर बाधित करने की कोशिश की है। मार्क्सवादी जुमले उछालते हैं और सही काम का विरोध करते हैं, जबकि ज़मीनी स्तर पर कभी कुछ नहीं करते। जो भी हो, न इनके समर्थन का कोई मतलब है और न ही इनके विरोध का। भूलना नहीं होगा, सुधारवाद की क्रांति की पूर्व-पीठिका तैयार करने में बड़ी भूमिका रही है। इसका इतिहास इन्हें देखना चाहिए। आज की स्थिति में जनता को राहत की जरूरत है और अरविंद केजरीवाल अगर उसे थोड़ी राहत दे पाने में भी सफ़ल रहते हैं, तो यह योगदान उनका उल्लेखनीय माना जाएगा।

जहां तक राष्ट्रीय राजनीति पर केजरीवाल की इस जीत का असर पड़ने की बात है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। असर तो पड़ेगा ही। खासकर युवा वर्ग अरविंद केजरीवाल की जीत से काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहा है। अरविंद स्वयं युवा हैं। युवा ही परिवर्तन का वाहक बनता रहा है। मुलायम, नीतीश, लालू, ममता में अब दम नहीं। इनके दिन लद चुके। नहीं लदे तो जल्दी ही लद जाएंगे। ये जातिवाद, अल्पसंख्यकवाद और अपराधियों से गठजोड़ कर सत्ता चलाते रहे हैं और अब खुद में बदलाव नहीं ला सकते। ये कहते तो ख़ुद को समाजवादी हैं, पर हक़िक़त है कि ये सामंती प्रवृत्ति के हैं और ग़रीब जनता को बरगला कर अपना उल्लू सीधा करते रहे हैं। अब इनका ज़माना लदे तो नया ज़माना आए। क्या अरविंद केजरीवाल से ये उम्मीद की जा सकती है कि वह नए किस्म के विकल्प का प्रसार निकट भविष्य में पूरे देश में करेंगे या दिल्ली तक ही ख़ुद को सीमित रखेंगे? जाहिर है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का विस्तार राष्ट्रीय फ़लक पर करना चाहते हैं तो इसमें समय लगेगा। ये रातोंरात हो पाना संभव नहीं है। दूसरे, उन्हें अपना वैचारिक आधार भी स्पष्ट करना चाहिए।

वर्त्तमान सत्ता की मुख्य चालक शक्ति पूंजीवाद है। साथ ही, यह अंतरराष्ट्रीय पूंजी से आबद्ध है। जब तक इस पर चोट नहीं की जाएगी तो वर्तमान ढांचे में जनता को विशेष राहत नहीं मिलने वाली। जितने मठ-मंदिर है, जहां लुटेरे बैठकर अय्याशी कर रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवल उन्हें पकड़ कर सबक सिखा सकते हैं? क्या दिल्ली में दर्द का जो समंदर है, उसमें डूब रहे लोगों को राहत की खेप पहुंचा सकते हैं। प्रवासी मज़दूरों को उनका सही मेहनताना दिला सकते हैं? ऐसी कई बातें हैं, जो तय करेंगी कि अरविंद केजरीवाल जन अपेक्षाओं पर किस हद तक खरे उतर पाते हैं। अगर वो इन अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरते तो फ़िर लुटेरे राजनेताओं के लिए अवसर अनुकूल होंगे। अरविंद केजरीवाल सुधारवाद के पैरोकार हैं, इसलिए हम उनसे क्रांतिकारी अपेक्षाएं नही रख सकते, पर सुधार भी वो लागू कर दें तो क्रांति के लिए ज़मीन मजबूत होगी।

गतांक की चीरफ़ाड़

मज़दूर मोर्चा का 1-15 फ़रवरी 2015 का अंक मिला, जिसमें समसामयिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख पढने को मिले। 'पांच साल केजरीवाल या मोदी-बेदी की खड़ताल-सरकार नहीं लोकतंत्र है दांव पर' तथा 'दिल्ली में मोदी को केजरीवाल की कड़ी चुनौती' लेखों द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव की स्थिति का उचित मूल्यांकन किया गया है। यह चुनाव भाजपा विशेषकर मोदी व अमितशाह के लिये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। इस चुनाव को जीतने के लिये लगभग दो दर्जन केन्द्रीय मंत्री, सौ से अधिक सांसद, आर एस एस के स्वयं सेवक तथा अन्य राज्यों से भी कार्यकर्ता भारी तादाद में तैनात किए गए।

भाजपा का चुनाव प्रचार अभियान भी केन्द्रीय संगठन (अमितशाह) के हाथ में रहा। दूसरी तरफ़ आप व केजरीवाल ने अपने 49 दिन के शासन काल की उपलब्धियों व दिल्ली के विकास की योजना को जनता के सामने रखा तथा वे जनता से अपना संवाद स्थापित करने में सफल रहे। इसके अतिरिक्त भाजपा के नकारात्मक प्रचार तथा केजरीवाल पर किए जा रहे व्यक्तिगत आक्रमण का जवाब देने की अपेक्षा उन्होंने सकारात्मक प्रचार पर बल दिया। उसके फलस्वरूप केजरीवाल व आप को विधान सभा में कुल 70 में 67 सीटें प्राप्त हुई तथा 54 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए।

भाजपा का लगभग सफ़ाया हो गया जिसे केवल तीन सीट मिली तो 130 वर्ष पुरानी कांग्रेस का तो सूपड़ा साफ़ हो गया जिसका खाता भी नहीं खुल पाया। 'आप' की इस ऐतिहासिक जीत से 'आप' के प्रति जनता की भारी आशाएं बंधी हैं तथा 'आप' की जवाबदेही बढी है। अब देखना है कि इस वर्तमान ढांचे में केजरीवाल केन्द्र के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न करते हैं या समन्वय स्थापित करके अपने कार्यक्रम को लागू कर पाते हैं।

लेख 'केजरीवाल सिर्फ़ मुख्यमंत्री या भावी प्रधानमंत्री द्वारा केजरीवाल की कार्यप्रणाली का अमरीकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में सटीक विश्लेषण किया गया है। केजरीवाल व 'आप' ने ना तो अपनी विचारधारा स्पष्ट की है और न ही वे देश में किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं इसका कोई जिक्र किया है। वे केवल मुद्दों पर आधारित राजनीति कर रहे हैं।

लेख 'खबर दार-राजपथ पर जन गण मन के पांच सितारा पहरूए' द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के संदर्भ में आम जनता की अवहेलना तथा विशिष्ट जनों व शासक वर्ग की शान-शौकत पर कटाक्ष किया गया है।

रेल विभाग की बुलेट ट्रेन झांकी द्वारा मुंबई से अहमदाबाद तक 6300 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली बुलेट ट्रेन पर गर्व प्रदर्शित किया गया जबकि आम आदमी द्वारा यात्रा करने वाली ट्रेनों की क्या स्थिति है इस पर कोई विचार नहीं किया जाता। यह नज़ारा दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखा जा सकता है। पूरी ट्रेन में अनारक्षित डब्बों की संख्या बहुत कम होती है जिसमें चढने के लिये यात्रियों की भारी भीड़ होती है और उनमें मारा-मारी भी हो जाती है। साधारण श्रेणी के यात्रियों को राहत देना व मानव रहित रेलवे क्रासिंग पर नियंत्रण करना मोदी सरकार के एजेंडा पर नहीं है। यह विचारणीय प्रश्न है कि बुलेट ट्रेन में यात्रा कर पाने की क्षमता देश की कितने प्रतिशत जनता में है।

लेख 'एक आइकन का अवसान' में एक पूर्व पुलिस अधिकारी तथा भाजपा के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी की पुलिस अफ़सर के रूप में पेशेवर शाख का सटीक विश्लेषण किया गया है। भाजपा ने मजबूरी में किरण बेदी को अपनी पार्टी में शामिल करके मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव में केजरीवाल बनाम किरण बेदी चुनावी लड़ाई पेश करने की कोशिश की, परंतु वास्तव में जनता से वोट मोदी के ही नाम पर मांगे गए। समाचारपत्रों में बड़े-बड़े इश्तिहार दिए गए जिनमें लिखा था 'चलो-चले मोदी के साथ'। इसके अतिरिक्त भाजपा बार-बार कहती रही कि 'जो देश सोचता है, वह दिल्ली सोचती है'।

लेख 'एन आई टी में जुआ सट्टा व सूदखोरी नहीं थम रही' द्वारा सट्टेबाज़ों, शराब माफ़ियों, जुआरियों, सूदखोरों व अन्य अपराधियों का पुलिस विभाग के साथ सांठ-गांठ का सांगोपांग पर्दाफ़ाश किया गया है। यह स्थिति केवल फ़रीदाबाद की ही नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति लगभग पूरे देश में व्याप्त है। इस स्थिति के लिये राज्य व केन्द्र की सरकारें पूरी तरह उत्तरदायी हैं, फ़िर चाहे वह सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो क्योंकि पुलिस व उक्त अपराधियों को किसी न किसी रूप में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है।

कविता 'लिखा जाएगा गणतंत्र का नया घोषणापत्र' द्वारा देश की वर्तमान व्यवस्था व गणतंत्र दिवस समारोह पर उचित कटाक्ष किया गया है। मज़दूर मोर्चा नाम को सार्थक करते हुए मज़दूरों के हितों के मुद्दे उठाते हुए मज़दूरों की चिकित्सा सेवा के सम्बन्ध में ई एस आई मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पर लेख लगातार प्रकाशित किए गए हैं। इस अंक में भी लेख '16 लाख मज़दूरों को किस गुनाह की सज़ा दे रहा है ई एस आई निगम' तथा 'मैट्रो अस्पताल द्वारा पुलिसिया डंडे से मज़दूरों का दमन' प्रकाशित हुए हैं, परंतु केन्द्र व राज्य की भाजपा सरकार के कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही है। अन्य प्रकाशित लेख भी प्रशंसनीय व प्रेरणादायक हैं।

प्रो. जुगल किशोर गुप्ता